

तकनीकी प्रपत्र

क्र.सं.	विवरण	
1.	फर्म का नाम व पता टेलीफोन नं० ई-मेल पता	
2.	फर्म की स्थिति एकांकी/पार्टनरशिप/प्रा.लि./क० आदि	
3.	अमानता राशि का विवरण (डी.डी/चालान का विवरण प्रस्तुत करे।)	
4.	GST Certificate & Last Month GST Return (प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करे।)	
5.	फर्म द्वारा WPC/Department of Telecom से जारी वैद्य लाईसेंस (WOL) की छायाप्रति संलग्न करे।	
6.	विगत 3 वर्ष में वार्षिक औसत न्यूनतम टर्न ओवर 16 लाख रुपये प्रति वर्ष कार्य किया हो (सीए ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति)	
7.	फर्म का पैनकार्ड नं. की छायाप्रति संलग्न करे।	
8.	केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों में विगत तीन वर्षों में से किसी 01 वर्ष में समान प्रकृति के कार्य करने का अनुभव/संतोषजनक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करे।	
9.	किसी भी सरकारी विभाग, संस्था बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथवा उपक्रम में वर्तमान में फर्म ब्लैक-लिस्टेड/डी-बार अथवा डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए जिसका शपथ-पत्र देना अनिवार्य है। (100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र)	
10.	फर्म द्वारा एनेक्ज़र ए, बी, सी डी एवं ई हस्ताक्षर मय सील संलग्न करे।	Validity unknown Signature valid

हस्ताक्षर

नाम.....

फर्म का पता.....

Digitally signed by K. S. Choudhary

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2024.08.27 11:56:51 IST

Reason: Approved

उपायुक्त (स्टोर)

नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

नगर निगम ग्रेटर जयपुर में वायरलैस सेट्स का संचालन, संधारण एवं मरम्मत कार्य की दर संविदा हेतु

नियम एवं शर्त :-

1. नगर निगम जयपुर(ग्रेटर) के कार्यालय उपयोगार्थ के हेतु 225 नग 800 MHz Handeheld (PMRTS Trunk Radio/Wireless) फिक्स वायरलैस सेट एवं वायरलैस हैंड सेट संचालन, संधारण मरम्मत कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित करता है।
2. उक्त निविदा ऑनलाईन वेबसाईड www.eproc.rajaasthan.gov.in से भरी जा सकती है।
3. निविदादाताओं को निविदा शुल्क, अमानता राशि एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org पर Submission Date and time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्कैन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जायेगा।
4. निविदादाता के पास WPC/ Department of Telecom से जारी वैद्य लाईसेन्स (WOL) होना अनिवार्य है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदादाता फर्म के मालिक/फर्म का पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. निविदादाता को विगत तीन वर्षों (2021-22, 2022-23 तथा 2023-24) में निविदा राशि का वार्षिक औसत न्यूनतम 50 प्रतिशत टर्न ओवर प्रतिवर्ष का होना आवश्यक होगा। इस हेतु सी.ए. से प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. निविदादाता द्वारा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशाषी संस्थाओं/अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों में विगत तीन वर्षों में से किसी 01 वर्ष में समान प्रकृति के कार्य का अनुभव संबंधी दस्तावेज अथवा सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी अनुभव/संतोषजनक कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रतियां।
8. निविदादाता का जीएसटी विभाग द्वारा जारी जीएसटी सर्टिफिकेट मय नवीनतम जीएसटी रिटर्न एवं इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. सफल निविदादाता द्वारा आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में आरटीपीपी नियमानुसार प्रतिभूति राशि (कुल 05 प्रतिशत) जमा करवानी होगी एवं उक्त कार्य का अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. नगर निगम ग्रेटर जयपुर के उपयोग में आने वाले 800 MHz Handeheld (PMRTS Trunk Radio/Wireless) फिक्स एवं हैंडल हैंड अधिकतम 225 या जो भी उपयोग में लिये जाने वाले वायरलैस सेटों की संख्या (जो भी कम हो) के अनुसार फर्म को भुगतान किया जायेगा।
11. निविदा की सभी नियम एवं शर्तें मान्य होगी।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में माननीय आयुक्त महोदय का निर्णय मान्य एवं अन्तिम होगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर शहर
14. उक्त निविदा में आरटीपीपी नियम 2012 तथा 2013 एवं

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K. S. Choudhary
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2024.08.15 15:56:51 IST
Reason: Approved

15. विड बैलेडीटी की अवधि 90 दिवस तक मान्य होगी।
16. निविदादाता को प्रतिदिन 24 घण्टे रेडियो ट्रकिंग सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
17. रेडियो ट्रकिंग सुविधा को 24 घण्टे चालू रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
18. रेडियो ट्रकिंग सुविधा के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
19. राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 76 के अनुसार कार्य आदेश जारी दिनांक से 15 दिवस की अवधि में रूपये 1000 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के खर्चे पर करार का निष्पादन करना होगा।
20. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-75 के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति एवं अनबेलेन्स बिड के मामले में नियम -75ए के अनुसार अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी।
21. रेडियो रिपेयर संबंधी पहलुओं एएमसी एवं अन्य सामान कम्पनी द्वारा देखे जाएंगे। कम्पनी की जिम्मेदारी है कि वे जरूरी सामान उपलब्ध करवाए, रेडियो रिपेयर करवाएं एवं कम से कम समय में हर समय सेवाएं उपलब्ध करवाएं। सम्पूर्ण सेवाएं 2 घण्टे से अधिक समय तक बंद रहने पर आनुपातिक कटौती होगी यह कटौती उस समय के लिए होगी जितनी देर सेट उपयोग लायक नहीं रहा। वायरलैस सेटों पर दो घण्टे से अधिक समय के रेडियो ट्रकिंग सुविधा खराब रहने पर 100/-रु प्रति घण्टा प्रति वायरलैस सेट के हिसाब से कटौती की जावेगी।
22. रेडियो ट्रकिंग सुविधा 48 घण्टें से ज्यादा खराब रहती हैं तो उक्त सेट के स्थान पर कार्य व्यवस्था हेतु अन्य सेट उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा प्रति सेट के हिसाब से खराब रहे दिवसों की औसतन कटौती की जावेगी।
23. रेडियो ट्रकिंग सुविधा 03 दिवस से अधिक समय तक खराब रहने पर फर्म को पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त की जा सकेगी।
24. निविदा में प्राप्त दरों के आधार पर किये जाने वाले अनुबंध की अवधि कार्यादेश की तारीख से 01 वर्ष तक होगी। इसके पश्चात् कार्य संतोषजनक होने पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
25. तकनीकी निविदा में सक्षम होने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
26. राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी किये गये निर्देशों की पालना निविदादाता को करनी होगी।
27. संवेदक/फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा फर्म की अनुबन्ध अवधि/कार्यादेश को नोटिस देकर बीच में ही समाप्त किया जा सकता है।
28. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाले यंत्र दोष रहित होना आवश्यक है ताकि संचालन के दौरान बाधा न आवें। इस हेतु अन्य सेट अतिरिक्त स्पेयर में मौके पर रखने होंगे, जिसका कोई चार्ज देय नहीं होगा।
29. दर निविदा अनुबंध की शर्तों की अवहेलना करने पर निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि स्वीकृत निविदा दाताओं की अमानता राशि जप्त कर पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू करे।
30. किसी भी दर संविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा।

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by K. S. Choudhary
 Designation : Deputy Commissioner
 Date: 2024.06.11 11:51:51
 Reason: Approved

31. यह दर निविदा वार्षिक दर संविदा के लिए की जा रही है। वर्ष भर में स्वीकृत दर के आधार पर निगम आवश्यकतानुसार कार्य करा सकेगा।
32. इस करार से उत्पन्न समस्त विवादों तथा इस करार के निर्वचन से संबंधित समस्त प्रश्न नगर निगम, ग्रेटर जयपुर द्वारा निर्णित किये जायेंगे। और निगम का निर्णय अंतिम होगा।
33. संवेदक को किसी भी राजकीय संस्था विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथवा उपक्रम में वर्तमान में ब्लैक-लिस्टेड/डी-बार अथवा डिफाल्टर घोषित नहीं किया होना चाहिए इस संबंध में 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पैपर पर नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
34. निविदादाता को निविदा की शर्तों एवं निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील करना अनिवार्य होगा।
35. निविदादाता द्वारा निविदा राशि की 02 प्रतिशत अमानता राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति घोषणा पत्र की हार्डकॉपी फर्म द्वारा निर्धारित समय, दिनांक पर कार्यालय में जमा करानी होगी।
36. निविदादाता को एनेक्ज़र ए, बी, सी डी एवं ई हस्ताक्षर मय सील संलग्न करना अनिवार्य होगा।
37. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स 2013 में दिये गये निर्देश निविदा में लागू होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(कविता चौधरी)
उपायुक्त(स्टोर)
नगर निगम, ग्रेटर जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Kaviya Choudhary
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2024.08.28 15:56:51 IST
Reason: Approved

Item Rate BoQ

Tender Inviting Authority: DEPUTY COMMISSIONER STORE GREATER

Name of Work: नगर निगम ग्रेटर जयपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु फिक्स एवं हैंडल हैंड वायरलैस सेटो का संचालन, संधारण एवं मरम्मत कार्य की दर संविदा हेतु

Contract No: DEPUTY COMMISSIONER STORE GREATER/2024-25/05

Name of the Bidder/
Bidding Firm /
Company :

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	कार्य/सामान का विवरण	तादाद	दर प्रति नग (जी एसटी सहित)	TOTAL AMOUNT in Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम ग्रेटर जयपुर के कार्यालय उपयोगार्थ आ रहे एवं आने वाले 800 MHz Handeheld (PMRTS Trunk Radio/Wireless) फिक्स एवं हैंडल हैंड वायरलैस सेटो का संचालन, संधारण एवं मरम्मत कार्य	225		0.00	INR Zero Only
Total in Figures		Validity unknown		Signature valid	0.00 INR Zero Only
Quoted Rate in Words		Digitally signed by Kavita Choudhary Designation : Deputy Commissioner Date: 2024.08.21 17:56:51 IST Reason: Approved			

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure E

Clause 1: Fair Wage Clause

- (a) The Contractor shall pay not less than fair wages/minimum wages to labours engaged by him on the work as revised from time to time by the Government, but the Government shall not be liable to pay any thing extra for it except as stipulated in price escalation clause (clause 45) of the agreement.

Explanation: "Fair Wage" means minimum wages for time or piece work, fixed revised, by the State Government under the Minimum Wages Act, 1948.

- (b) The Contractor shall, notwithstanding the provision of any contract to the contrary, cause to be paid fair wages to labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-contractors in connection with the said work as if the labourers have been immediately or directly employed by him.
- (c) In respect of all labourers, immediately or directly employed on the work, for the purpose of the Contractor's part of this agreement, the Contractor shall comply with or cause to be complied with the Public Works Department Contractor's Labour Regulations made, or that may be made by the Government, from time to time, in regard to payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid, and unauthorised deductions, maintenance of wages register, wage card, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and other matters of a like nature.
- (d) The Engineer-in-charge shall have the right to deduct from the money due to the Contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a worker or workers, by reasons of non-fulfilment of the conditions of the contract, for the benefit of the worker or workers, non-payment of wages or of deductions made there from, which are not justified by the terms of the contract, or as a result of non-observance of the aforesaid regulations.
- (e) Vis-à-Vis the Municipal Corporation Jaipur, the Contractor shall be primarily liable for all payments to be made and for the observance of the regulations aforesaid, without prejudice to his right to claim indemnity from his subcontractors,
- (f) The regulations, aforesaid, shall be deemed to be part of this contract and any breach, thereof, shall be breach of the contract.

Clause 2: Contractor to engage technical staff

The Contractor shall engage the technical staff, as follows, on the contract works:-

- (a) For works costing Rs. 100 lac and above- One Graduate Engineer.
- (b) For works costing between Rs. 50 lac to Rs. 100 lac- One qualified diploma holder having experience of not less than 3 years.
- (c) For works costing between Rs. 15 lac and Rs. 50 lac- One qualified diploma holder.

The technical staff should be available at site, whenever required by Engineer-in-charge to take instructions.

Clause 3 :

The Contractor shall comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961, and the Rules and Orders issued, there under, from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

Clause 4: Safety Code

The Contractor shall follow the safety code of electricity Strictly.

Clause 5:

Near Relatives barred from tendering

The Contractor shall not be permitted to tender for works in Circle, in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Superintending Engineer and Assistant Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons, who are working with him in any capacity, or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Organization/Department. Any breach of this condition by the Contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of the Department. If such facts is noticed (a) before sanction of tender, his offer shall be declared invalid and earnest money shall be forfeited, (b) after sanction of the tender then the tender sanctioning authority may at his discretion forfeit his earnest money, performance guarantee, security deposit and enlistment deposit and the work/remaining work may allot to any registered contractor on the same rates as per rules.

Note: By the term 'near relative' is meant wife, husband, parents and grand-parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 6: Retired Gazetted Officers barred for 2 years

No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer, employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of Rajasthan, is allowed to work as a Contractor for a period of 2 years of his retirement from Government service without the previous permission of Government of Rajasthan. The contract is liable to be cancelled, if either the Contractor or any of his employees is found, at any time, to be such a person, who had not obtained the permission of Government, as aforesaid, before, submission of the tender or engagement in the contractor's service, as the case may be.

Clause 7: Quality Control

The Municipal Corporation Jaipur shall have right to exercise proper Quality Control measures. The Contractor shall provide all assistance to conduct such tests and shall bear the cost of all tests.

Clause 8:

The work (whether full constructed or not) and all materials, machines, tools and plant, scaffolding,

temporary buildings and other things connected therewith, shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer- in -charge, and a certificate from him, to the effect, obtained.

Clause 9: Death of Contractor

Without prejudice to any of the rights or remedies under the contract, if the Contractor dies the legal heirs of the Contractor or the Chief Engineer or duly authorised Engineer shall have the option of terminating the contract without any compensation.

Clause 10 : Force Majeure

Neither party shall be liable to each other, for any loss or damage, occasioned by or arising out of acts of God such as-unprecedented floods, volcanic eruptions, earthquake of other invasion of nature and other acts.

Clause 11: General Discrepancies and errors:

In case of percentage rate tenders, if there is any typographical or clerical error in the rates shown by the department in the "G" Schedule. the rates as given in the basic Schedule of Rates of the Department for the area shall be taken as correct.

Clause 12 : Post payment Audit & Technical Examination:

The Government shall have right to provide a system of per-check of Contractor's bill by a specified Organization, and payment by an Engineer or an Accounts Officer/ Sr. Accounts Officer/ Chief Accounts Officer/ Financial Advisor, as the Government may in its absolute discretion prescribe. Any over-payments/ excess payment detected, as a result of such per-check post-check of Contractor's bill, can be recovered from the contractor's bills in the manner, herein before provided and the Contractor will refund such over/ excess payments.

Clause 13 : Check Measurements:

The department reserves to itself, the right to prescribe a scale of check measurement of work in general, or specific scale for specific works of by other special orders (about which the decision on the department shall be final) Checking of measurement by superior officer shall supersede measurements by the subordinate officer and the former will become the basis of the payment. Any over/excess payment detected, as a result of such check measurement or otherwise at any stage up to the date of completion and the defect removal period specified else-where in this contract, shall be recoverable from the Contractor, as any other dues payable to the Government.

Clause 14: Check Measurements:

The Contractor in course of the work should understand that all materials e.g. stone, bricks, steel and other materials obtainable in the work by dismantling etc. will be considered as the property of the Government and will be disposed off to the best advantage on the Government. As per direction of the Engineer-in-Charge.

Clause 15: Recovery from Contractors:

Whenever any claim against the Contractor for the payment of a sum of money arises out of or under the contract, the Department shall be entitled to recover such sum by appropriation in part or whole of the Performance Guarantee and / or Security Deposit. Security Deposit at the time of enlistment of the Contractor. In the event of the security being insufficient, or if no security has been taken, thereafter, may become due to the Contractor, under this or any other contract with the Governor of Rajasthan. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable the Contractor shall pay to the Department on demand the balance remaining dues.

The department shall, further, have the right to affect such recoveries under Public Demands Recovery Act.

Clause 16: Jurisdiction of Court:

In the event of any dispute arising between the parties hereto, in respect or any of the matters comprised in this agreement, the same shall be settled by a competent court having jurisdiction over the place, where agreement is executed any by no other court, after completion of proceedings under Clause 23 of this contract.